राष्ट्रपति ओबामा का गणतंत्र दिवस दौरा

डॉ. स्तुति बनर्जी *

प्रस्तावना

भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने हेतु प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर राष्ट्रपति बराक ओबामा इस समारोह के सम्मानित अतिथि बनने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति रहे और उस घनिष्ठ संबंध का संकेत दिया जो अमरीका भारत के साथ अनुसरण करना चाहता है। ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से निमंत्रण स्वीकार करने का असामान्य तरीका उस सहजता का भी संकेत है जो दोनों नेता एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। इन्होंने एक स्वस्थ कार्यात्मक संबंध स्थापित किए हैं जो सितंबर, 2014 में प्रधान मंत्री मोदी के अत्यंत सफल अमरीकी दौरे से स्पष्ट हो गया था। ट्विटर पर की गई बातचीत उस बंधन/संबंध को प्रदर्शित करती है जिसे स्थापित करने में ये (दोनों) समर्थ रहे हैं और जो सरकारी प्रोटोकॉल में रहने की आवश्यकता के दायरे से बाहर निकल गया है।

यह राष्ट्रपति ओबामा का दूसरा दौरा होगा जो एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कि पहली बार कोई अमरीकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान भारत की यात्रा दो बार करेगा। उनका पहला दौरा वर्ष 2010 में हुआ था, जब उन्हें संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला था। (सबसे ज्यादा) आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति ओबामा ने ऐसे समय में निमंत्रण स्वीकार किया है जब उनसे सामान्य तौर पर 'स्टेट ऑफ द यूनियन ऐड्रेस' के लिए वाशिंगटन में होने की आशा की जाती है। यह संबोधन एक वार्षिक कार्यक्रम/समारोह है जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति कार्यकारी शाखा के विभिन्न विभागों की प्रशासनिक रिपोर्टें और बजट व आर्थिक संदेश सभापटल पर रखते हैं। यह संविधान के तहत एक अपेक्षा है जिसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति "समय-समय पर संघीय राष्ट्र संबंधी सूचना कांग्रेस को उपलब्ध कराएंगे

और उनके विचारार्थ ऐसे उपायों की संस्तुति करेंगे जिसे वे तत्काल किए जाने हेतु आवश्यक मानते हैं।" (अनुच्छेद 2, धारा 3, खंड 1)[1] ऐसे मौके पर (देश से) बाहर जाना उस महत्व का एक और संकेत है, जो वाइटहाउस द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को दिया जा रहा है।

क्षेत्रीय सुरक्षा

इस दौरे के संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत क्षेत्रीय देशों को यह दर्शाने में सक्षम रहा है कि जहां इसने पड़ोस में अपने संबंधों को विकसित करने को महत्व दिया है वहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यह शक्तिशाली साझेदारों/भागीदारों से वंचित नहीं है। भारत सरकार ने पड़ोस के राष्ट्रों के साथ संबंधों में सुधार करने को अपनी नीतिगत पहल बनाया है। प्रधान मंत्री मोदी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, और सरकार के उच्च श्रेणी के पदाधिकारी भारत के संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने तथा इसे और घनिष्ठ बनाने के लिए पड़ोसी राष्ट्रों का दौरा करते रहे हैं।

पाकिस्तान

राष्ट्रपति ओबामा के दौरे से जो सांकेतिक छवि बनेगी, यह दौरा उससे कहीं ज्यादा प्रभावकारी साबित होगा। यह तथ्य कि भारत राष्ट्रपति ओबामा से इस निमंत्रण को स्वीकार करवाने में समर्थ रहा है, वह जापान जैसे भारत के मित्र और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों द्वारा आसानी से भूलाया नहीं जाएगा। नि:संदेह, यह पाकिस्तान के लिए निराशाजनक है कि आतंकवाद के विरूद्ध अमरीका के संघर्ष में उसका प्रमुख सहयोगी होने का दावा करने के बावजूद, एक बार फिर से राष्ट्रपति ओबामा द्वारा इसे (पाकिस्तान) नज़रअंदाज किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी टुकड़ियों की वापसी के साथ ही, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की महत्ता कम हो गई है जिसके जरिए सामग्रियों की आपूर्ति होती थी, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अफगानिस्तान को लेकर भविष्य में की जानेवाली किसी भी शांति पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि पाकिस्तान अपने पक्ष में मत तैयार करके यह सुनिश्चित करने में समर्थ हो जाए कि राष्ट्रपति ओबामा अपने पूर्ववर्तियों की तरह कुछ घंटों के लिए ही सही, इस्लामाबाद का भी दौरा करेंगे। ऐसे किसी छोटे पड़ाव से अमरीका-पाकिस्तान गठबंधन को कोई महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि हासिल होने की संभावना नहीं है।

पाकिस्तान भारत और अमरीका दोनों के लिए समान चिंता का विषय बना हुआ है। परमाणु संपन्न राष्ट्र द्वारा आतंकवाद को समर्थन दिया जाना साबित हो चुका है, जिसका सबसे गंभीर प्रभाव/परिणाम भारत ने ही भुगता है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका भी इसके परिणामों से डरता है। यह तथ्य कि

ओसामा बिन लादेन ऐबटाबाद में पाया गया था, जहां वह पाकिस्तान की कुलीन सैन्य संस्था से अधिक दूरी पर नहीं रह रहा था, और इस तथ्य का तथाकथित रूप से पाकिस्तानी सरकार अथवा उसकी विभिन्न खुफिया एजेंसियों की जानकारी में नहीं होना उस समर्थन को साबित करता है जो आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में प्राप्त है। वर्ष 2008 के मुंबई हमले, जिसमें अमरीकी नागरिक भी मारे गए थे, के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी के मामले में हाल में प्रदर्शित उदारता से भारत को नाराजगी हुई है और इसे फलते-फूलते आतंकवादी संगठनों को रोक पाने में पाकिस्तान सरकार की अक्षमता के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे वातावरण में भारत-अमरीका के घनिष्ठ संबंध इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को सुदृं करने में महत्वपूर्ण कारक (सिद्ध) होंगे। यह एशिया और विश्व में उन्मुक्त, संतुलित तथा समग्र सुरक्षा ढ़ांचे के निर्माण में सहायक होगा। यह एक ऐसा लक्ष्य होगा जो दोनों राष्ट्रों के साझा हित में है।[2]

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान भारत-अमरीका संबंधों के लिए चुनौती बना रहेगा। यह (अफगानिस्तान) इस क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने और तालिबान को फिर से उभरने से रोकने के प्रयासों में दोनों राष्ट्रों को एक कार्यनीतिक समाभिरूपता प्रदान करता है। अमरीकी टुकड़ियों की वापसी और अफगानी राष्ट्रपति चुनावों के माध्यम से सत्ता का सफल हस्तांतरण इस देश में दो महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हैं। तथापि, साझा हितों के बावजूद, अफगानिस्तान में भारत और अमरीका के बीच सहयोग अपनी क्षमता से अत्यधिक कम रहा है। भारत ने अपने आप को अफगानिस्तान के विकास में एक विश्वसनीय द्विपक्षीय भागीदार के रूप में बदल लिया है। अफगानिस्तान को लेकर भारत और पाकिस्तान के हितों में टकराव होता रहता है। भारत ने पाकिस्तान के प्रभाव को न्यूनतम करने और कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के विरूद्ध भारत की लड़ाई में सुरक्षा भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा निवेश किया है। नई दिल्ली के सक्रिय संपर्क का ही परिणाम है कि आज यह काबुल के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध साझा करता है। दूसरी ओर, पाकिस्तान अभी भी तालिबान को एक महत्वपूर्ण कारक मानता है और इसकी कार्यनीति भारत के प्रभाव को न्यूनतम करने की रही है। यह दौरा दोनों राष्ट्रों के नेताओं को अफगानिस्तान में सत्ता के शांतिपूर्ण परिवर्तन संबंधी नीति तैयार करने का अवसर प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में दोनों देशों के मिलकर काम करने पर चर्चा हो सकती है।

चीन

सत्ता केन्द्र एटलांटिक और यूरोप से हटकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र की ओर आ रहा है। आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही मामलों में चीन का अभ्युदय उल्लेखनीय रहा है। इसके अभ्युदय के साथ ही, इसने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों का विस्तार किया है और अब यह सामान्य रूप से विश्व स्तर पर और विशेष रूप से

एशिया व प्रशांत क्षेत्र में अमरीका को चुनौती दे रहा है। भारत एशिया में शक्ति संतुलन में चीन का पलड़ा भारी न हो, इसे अमरीका द्वारा सुनिश्चित करने का विरोध नहीं करेगा। भारत के लिए चीन का यह बढ़ता प्रभाव चिन्ता का कारण है। भारत और अमरीका दोनों ही चीन के विकास पर नियंत्रण चाहते हैं और यद्यपि भारत ने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि यह चीन को दबाने की अमरीका की किसी भी नीति का हिस्सा नहीं बनेगा, फिर भी, भारत यह सुनिश्चित करने में अमरीका का विरोध नहीं करेगा। अमरीका के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को विकसित करने और आपसी लंबित मुद्दों को सुलझाने की कार्रवाई जारी रखने की आवश्यकता है।

यह तथ्य महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रपति ओबामा भारत के सैन्य पराक्रम की समीक्षा करेंगे जो इस परेड के दौरान परंपरागत रूप से राष्ट्र को प्रदर्शित किया जाता है और इसका महत्व चीन जैसे इस क्षेत्र के राष्ट्रों के लिए कम नहीं होगा। यह इस तथ्य के मद्देनज़र विशेष रूप से लक्षणीय है कि भारत और अमरीका अब एक दूसरे के साथ मिलकर सबसे अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यासों को अंजाम दे रहे हैं; भारत अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए अमरीका की ओर देख रहा है, जबकि अमरीका भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का भागीदार बनना चाहता है। भारतीय वायुसेना परिवहन विमान के रूप में लॉकहीड सी–130जे और बोइंग सी-17 का इस्तेमाल करती है और भारतीय नौसेना के पास पी-8आई *पोसिडन* समुद्री गश्ती विमान है, जिससे यह अरब सागर में किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि/कार्रवाई पर निगरानी रख सकती है। जल्दी ही अपाचे और सी हॉक हेलिकॉप्टर भारतीय सैन्य साजोसामान का हिस्सा होंगे।[3] अमरीका अब भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है और संभव है कि राष्ट्रपति ओबामा इनमें से कुछ सैन्य उत्पादों का प्रदर्शन देखें।

अमरीका के लिए यह दौरा उस महत्व को प्रदर्शित करता है जो भारत अमरीकी नीति-निर्माण/सोच में प्राप्त करने में सफल हो गया है और वह भूमिका, जो अमरीका चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में निभाए, विशेषकर, इस 'धुरी' के परिदृश्य में जो कि अमरीका ने एशिया और एशिया प्रशान्त के लिए अपनी नीतियों की घोषणा की है। अमरीका को उभरते चीन को संतुलित करने के लिए भागीदारों की जरूरत है। जापान कोरिया और फिलिपीन्स इस क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। बड़ी मात्रा में अमरीकी अनुदान तथा सहायता प्राप्तकर्ता 'देश' होने के बावजूद पाकिस्तान को एक भरोसेमंद सहयोगी की श्रेणी में अमरीका नहीं रख सकता है। अतीत के किसी दौर में अमरीका के लिए सहायक होने के बावजूद, चीन के साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संपर्कों का अभिप्राय यह भी है कि अमरीका इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहने का इच्छुक नहीं है। भारत और अमरीका अपने सांस्कृतिक मूल्यों: लोकतंत्र, मुक्त बाजार, बहुजातीय समाज और विविधता के

प्रति सहिष्णुता को साझा करते हैं।[4]

रक्षा संबंध

एक समाचार चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि ऐसी संभावना है कि राष्ट्रपति ओबामा की इस यात्रा के दौरान भारत और अमरीका एक नए 10 वर्षीय रक्षा ढ़ांचा करार पर हस्ताक्षर करें, यदि इस करार को प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति मिल जाती है। इस प्रकार के पहले करार पर वर्ष 2005 में रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी और रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफिल्ड के बीच हस्ताक्षर किया गया था। इस करार ने सुरक्षा वार्ता, सेवा स्तरीय आदान-प्रदानों, रक्षा अभ्यासों और रक्षा व्यापार तथा प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से परस्पर लाभप्रद रक्षा सहयोग की मजबूत नींव रख दी है।[5] भारत रक्षा व्यापार तथा प्रौद्योगिकी पहल (डीटीटीआई) के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पहल और व्यापार को नए करार में सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाने का आग्रह कर रहा है। भारत खरीद/प्रापण तथा क्रेता-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा मिलकर प्रौद्योगिकी विकास करने की ओर प्रयासरत है। इस नए करार से रक्षा भागीदारियों, सैन्य अभ्यासों, उच्चतर/उन्नत खुफिया साझेदारी के मुद्दे, समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भी समझौता होने की संभावना है। तथापि, उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी साझा करने में अमरीका की उदासीनता भारत के साथ अमरीकी भागीदारी पर प्रश्नचिन्ह लगा देता है।

हिन्द महासागर क्षेत्र 21वीं शताब्दी के कार्यनीतिक दिलचस्पी का क्षेत्र बन गया है। एशियाई अर्थव्यवस्था का विकास और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा आपूर्तियों सहित कच्ची सामग्रियों का इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाले यातायात में वृद्धि इसका कारण रहा है। अमरीका ने इस क्षेत्र पर अपनी कार्यनीतिक पकड़ बनाए रखा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमरीका अन्य नौसैनिक ताकतों की सहायता से अपने प्रभाव को ठोस बनाना चाहता है। अमरीका हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका पर विशेष जोर दे रहा है। भारत के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ प्रगति तथा संपन्नता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है जो समुद्री रास्ते से बड़े पैमाने पर होता है; इसी प्रकार ऊर्जा भी, जो इसके उद्योग जगत का प्राण है। सामुद्रिक संसाधनों का उपयोग करने की संभावनाओं और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ-साथ इन तथ्यों ने समुद्र पर अरसे से प्रतिक्षित इसकी निर्भरता को महसूस कराने में मदद की है। भारत के चारों तरफ समुद्र खतरे और अनिश्चितताओं से भरे हुए हैं; चाहे वह बड़े पैमाने पर जलदस्युता हो चाहे, समुद्री आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का प्रसार हो। भारत के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इस पृष्ठभूमि में हिन्द महासागर ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में

प्रमुखता हासिल कर ली है।[6]

राष्ट्रपति की जनवरी की यात्रा प्रधान मंत्री द्वारा सितंबर, 2014 में की गई यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। यह प्रतीकवाद से बढ़कर है और यह बयानबाजी से आगे निकलकर ठोस संबंधों का निर्माण जारी रखने के लिए नौकरशाही को प्रोत्साहित करती है। संयुक्त रक्षा विनिर्माण, असैनिक परमाणु वाणिज्य तथा व्यापार में नई सफलताएं सर्वाधिक आशाएं दिलाती हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने यह स्वीकार नहीं किया है कि इस यात्रा के दौरान किन्हीं नए करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, पर यह आशा की जाती है कि जारी करारों पर प्रगति होगी और राष्ट्रपति ओबामा अमरीकी उद्यमियों को भारत में निवेश करने में नए सिरे से उनकी रूचि जगाने में सक्षम होंगे।

असैनिक परमाणु सौदा

चर्चा के केन्द्र बिन्दु में लाए जाने की आवश्यकता वाला ऐसा ही एक करार असैनिक परमाणु सौदा है। अमरीकी विदेश विभाग की ओर से संकेत मिलते रहे हैं कि यह सौदा दोनों नेताओं के बीच बातचीत के विषयों में शामिल होगा। इस सौदे को दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध में निर्णायक मोड़ के रूप में माना गया है। तथापि, इस पर हस्ताक्षर होने के बाद से ही इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत और अमरीका द्वारा इस सौदे को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी की जानी हैं। वर्तमान में वेस्टिंगहाउस और जीई भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के साथ प्रारंभिक करारों पर बातचीत करने की प्रक्रिया में हैं। अमरीका ने दावा किया है कि भारत के घरेलू परमाणु दायित्व कानून उनके लिए चिन्ता के विषय हैं। दूसरी ओर, भारत ने इंगित किया है कि परमाणु इंधन पर नज़र रखने हेतु नए सिरे से द्विपक्षीय सत्यापनों की मांग अनावश्यक है। भारत ने स्वेच्छिक रूप से अपने असैनिक तथा रणनीतिक परमाणु सामग्रियों को पृथक कर लिया है और यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के अतिरिक्त प्रोटोकॉलों से भी सहमत है जिनसे परमाणु सामग्री और अपशिष्ट की जवाबदेही सुनिश्चित करनी है। ऐसी स्थिति में द्विपक्षीय सत्यापनों को अमरीकी प्रशासन द्वारा (सौदे को) लटकाने की चाल के रूप में देखा जा रहा है। आशा की जाती है कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण सौदे को कार्यान्वित करने में कुछ प्रगति होगी। यह अमरीकी प्रशासन द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सुलझाने के दृष्टिकोण से हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने और सतत विकास पर जो जोर दिया जा रहा है, उस से भी समापातित होगा। परमाणु ऊर्जा के साथ-साथ सौर ऊर्जा पर भी चर्चा होने की संभावना है।

आर्थिक संबंध

भारत के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रधानमंत्री द्वारा किए गए राजनयिक संपर्कों के अंत में

आया है जिसमें इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से लेकर प्रधान मंत्री आबे जैसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि मौजूदा सरकार विदेश नीति में अत्यंत सक्रियता से संलग्न है। प्रधानमंत्री मोदी के अधिकांश विदेश दौरों के केन्द्र में आर्थिक संबंध और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना रहा है। वे प्रवासी भारतीय समुदायों को भारत में आर्थिक संभावनाओं की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' के अपने नारे के साथ, प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि सरकार नए उद्यमों को सुविधाएं प्रदान करेगी और सुचारू रूप से काम करना सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव नौकरशाही लालफीताशाही कम करेगी। प्रधान मंत्री मोदी का अमरीका दौरा सफल रहा है जिसमें न केवल वे राष्ट्रपति ओबामा के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में सफल रहे हैं बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए (भारत) आगमन पर वीज़ा जैसे कतिपय उपायों की घोषणा भी की है।

जबकि यूरोप और चीन दोनों देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, भारत के लिए यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान करने का एक सुनहरा मौका है। विदेश सचिव जॉन केरी ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि अमरीका भारत-अमरीका व्यापार को 500 अरब अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष तक बढ़ाने के अवसरों की तलाश कर रहा है। यह वर्ष 2013 में रिपोर्ट की गई 97 अरब अमरीकी डॉलर के व्यापार में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। अमरीका आर्थिक संबंधों को 'लाभ-हानि रहित प्रतियोगिता' के रूप में नहीं बल्कि इसे वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने और एक दूसरे से व्यापार वार्ता के तरीकों में बदलाव के अवसर के रूप में देख रहा है ताकि इनके संबंध दोनों देशों के नेताओं द्वारा सोची गई नई उंचाइयों को प्राप्त कर सकें।[7]

भारत द्वारा देश के सीमा सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के मुद्दे को, जिसके अंतर्गत एच 1 बी और एल 1 वीज़ा शुल्कों को लगभग दोगुना कर दिया गया है, के संबंध में भी दौरे पर आ रहे अमरीकी राष्ट्रपति के समक्ष इसे वर्ष 2015 से आगे बढ़ाए जाने के लिए दबाव बनाने की संभावना है। अमरीकी सीमा सुरक्षा अधिनियम, जिसे वर्ष 2010 में लागू किया गया था और इसकी मियाद 30 सितंबर, 2014 को समाप्त होनी थी, को वर्ष 2015 तक बढ़ा दिया गया था। इस (अधिनियम) में कार्मिक के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशियों को रोजगार में रखने वाली फर्मों के लिए प्रति व्यक्ति वीज़ा शुल्क बढ़ाकर 4,500 डॉलर कर दिया गया, जिससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर कार्य करने (ऑन-साइट जॉब) के लिए अमरीका भेजना महंगा हो गया है।

निष्कर्ष

कुछ ऐसे विरोधी भी हैं जिन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा को बुलाना कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। वे उनकी (ओबामा) निम्न घरेलू लोकप्रियता दरों, रिपब्लिकनों के वर्चस्व वाली कांग्रेस के साथ उनके लगातार संघर्षों/टकराव तथा बड़ी संख्या में विदेश नीति लक्ष्यों, जो अपने अंजाम/मंजिल तक नहीं पहुंच सके, की ओर इशारा करते हैं। वे भारत को किए गए उनके वायदे की वैधता पर सवाल खड़े करते हैं। ये सब चिन्ता के जायज बिन्दु हैं। लकिन यह समझना होगा कि अपनी घटती लोकप्रियता के बावजूद वे अभी भी विश्व में सबसे शक्तिशाली कार्यालय के प्रभारी हैं। इनके पास दो वर्षों का कार्यकाल अभी शेष है और यह अमरीका के साथ घनिष्ठतर संबंधों का निर्माण करने हेतु भारत के लिए महत्वपूर्ण समय है, ऐसा संबंध जिससे भविष्य के राष्ट्रपति के पास, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, अमरीका की एशिया नीति तैयार करने में भारत को नज़रअंदाज करने अथवा बाइपास करने का विकल्प न हो। तथापि, एक उभरते रिपब्लिकन-नियंत्रित कांग्रेस के बावजूद, राष्ट्रपति ओबामा दो वर्षों के अपने शेष कार्यकाल में अमरीकी विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। उनके द्वारा हस्ताक्षरित अथवा वायदा किए गए किसी भी करार का, अपनी विचारधार के मतभेदों के बावजूद कांग्रेस द्वारा सम्मान किया जाएगा।

ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिन्हें विश्व के सबसे बड़े तथा प्राचीनतम (दोनों) लोकतांत्रिक (देशों) के बीच स्थापित इस रिश्ते द्वारा सुलझाया जाना है। तथापि, यह दौरा और इसका निहित महत्व दर्शाते हैं कि दोनों राष्ट्र उस विचारधारा के मतभेदों से बाहर निकल चुके हैं, जो शीतयुद्ध के वर्षों में संबंधों की अड़चन बने हुए थे। आज, ये एक विशेष भागीदारी साझा करते हैं, एक ऐसी साझेदारी, जिसे '21वीं सदी की भागीदारी को परिभाषित करने वाला' कहा गया है। दोनों राष्ट्रों के बीच अभी भी मतभेद हैं, जो इन्हें युक्रेन जैसे मुद्दों पर टेबल के विपरीत छोरों पर ले जाते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे विषय भी हैं, जैसे आतंकवाद, जिसपर (हम) इन्हें एक ही मंच से वार्ता करते पाते हैं। राष्ट्रपति ओबामा का भारत दौरा उस राजनयिक प्रगति की पृष्ठभूमि में हो रही है, जो भू-राजनीतिक मोर्चे पर चीन कर रहा है। पिछले वर्ष, मास्को और बीजिंग ने गैस के दो सौदों पर हस्ताक्षर किए। चीन पुराने 'सिल्क रोड़' को पुनर्जीवित कर रहा है, जो भूमि और समुद्र दोनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग रहा है। इस प्रकार, यह दौरा केवल सांकेतिक से कहीं अधिक है, यह दो बहुत शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच संबंधों को गहरा/घनिष्ठ बनाने की दिशा में तार्किक कदम है।

*डॉ. स्तुति बनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

समाप्ति नोट:

[1]संयुक्त राज्य अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव, "स्टेट ऑफ द यूनियन ऐड्रेस", http://history.house.gov/Institution/SOTU/State-of-the-Union/, 12 जनवरी 2015 को एक्सेस किया गया

[1] शिव शंकर मेनन, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी बंदोबस्ती (सितम्बर 2010), "भारत-अमेरिका संबंध" http://carnegieendowment.org/files/Ambassador_Menon's_Speech.pdf, 12 जनवरी 2015 को एक्सेस किया गया

[3] हुमा सिद्दीकी, "भारत-अमेरिका सम्मेलन में शीर्ष एजेंडे पर ऊर्जा और रक्षा व्यापार",http://www.financialexpress.com/article/economy/energy-defence-trade-to-top-agenda-at-indo-us-meet/29176/, 13 जनवरी 2015 को एक्सेस किया गया

[4]गुंजन बागला, "राष्ट्रपति ओबामा एक बार फिर भारत की यात्रा पर", http://www.huffingtonpost.com/gunjan-bagla/president-obama-to-visit-_b_6203982.html?ir=India, 2015 12 जनवरी को एक्सेस किया गया

[5]भारत का दूतावास, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, "भारत-अमेरिका रक्षा संबंध", https://www.indianembassy.org/pages.php?id=53, 13 जनवरी 2015 को एक्सेस किया गया,

[6] एडमिरल (सेवानिवृत्त) अरुण प्रकाश, "भारत की समुद्री सुरक्षा: भविष्य की चुनौतियां", http://www.idsa.in/keyspeeches/MaritimeSecurityOfIndiaFutureChallenges.html, 13 जनवरी 2015 को एक्सेस किया गया

[7] जॉन केरी, अमेरिकी विदेश मंत्री, "जीवंत/सक्रिय गुजरात उद्घाटन समारोह में टिप्पणी", http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/01/235772.htm, 12 जनवरी, 2015 को एक्सेस किया गया